



कार्यवाही की गई और ना ही कोई कारण बताओं नोटिस जारी किया गया और निर्णय पारित करते समय अपीलान्ट को सुनवाई व साक्ष्य का मौका दिया गया। अपीलान्ट की दुकान की जांच रिपोर्ट में यह दर्ज है कि दौराने जांच चिरंजीलाल उप सरपंच व सुरेश कुमार सरपंच आदि उपस्थित थे जिन्होंने अपने बयान दिये कि डीलर की वितरण व्यवस्था से हम सतुष्ट है। शिकायतकर्ता निहाल सिंह, रामप्रसाद, कृष्ण कुमार, श्याम सुन्दर जो कि एक ही परिवार के व्यक्ति है। रामप्रसाद ने माह जनवरी 20 में ग्राम पंचायत वधेरी कलां के सरपंच पद का चुनाव लडा था चुनाव में पराजित हो गया था। अपीलान्ट के परिवार में से सुरेश कुमार सरपंच पर का चुनाव जीता था, कृष्ण कुमार जो सरकारी कर्मचारी है जीएसएस वधेरीकलां का सचिव है। उसने भी अपना नाम खाद्य सुरक्षा की लिस्ट में दर्ज कराया हुआ है। जो खाद्य सुरक्षा की श्रेणी में नहीं आते है। जिला रसद अधिकारी ने अपीलीय निर्णय दिनांक 24.8.20 में जांच रिपोर्ट दिनांक 9.6.20 का वर्णन किया जाकर निर्णय का आधार बनाया है। अपीलान्ट के विरुद्ध कभी कोई ऐसा गंभीर आरोप नहीं रहा है कि अपीलान्ट का उचित मूल्य दुकान का प्राधिकार पत्र निरस्त किया जा सकें। अपीलान्ट को समुचित सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर नहीं दिया गया जबकि अवसर दिया जाना आवश्यक है। अपीलान्ट उचित मूल्य दुकानदार के कार्य को पूर्ण निष्ठा व ईमानदारी से करता चला आ रहा है। अपीलीय आदेश में जो तथ्य दर्ज किये वो गंभीर प्रवृत्ति के नहीं थे, केवल प्रकरण बनाने के लिए अपीलान्ट का लाईसेंस निलम्बित करने के लिए ही लगाये गये थे, जिनका वास्तविकता से कोई सम्बन्ध नहीं है। अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र निलम्बित होने से परिवार का पालन पोषण नहीं हो रहा है। जिला रसद अधिकारी, अलवर द्वारा अपीलान्ट को जो नोटिस दिया उसका जवाब पेश कर दिया गया है। अपीलान्ट पर लगाये गये आरोप गम्भीर प्रवृत्ति के नहीं है। जिला रसद अधिकारी, अलवर का फैसला विधि विरुद्ध तरीके से मनमर्जी एकतरफा में पारित किया गया है। अपीलान्ट पर लगाये गये आरोप गम्भीर प्रवृत्ति के नहीं है और न ही किसी प्रकार का गबन किया गया है। अपीलान्ट द्वारा कोई अनियमितता की गई है। जिला रसद अधिकारी, अलवर द्वारा मनमाने रूप से हठधर्मिता से आलोच्य आदेश पारित किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावें अपीलाधीन आदेशनिलम्बितफरमाया जावें, एवं अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र बहाल किये जाने के आदेश दिये जावें।

जिला कलेक्टर  
अलवर (राज०)

विभागीय पैरोकार ने अपील में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए निवेदन किया कि आदेश 1976 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 17 (सी) एवं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के आदेशों की स्पष्ट उल्लंघन किये जाने के कारण अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है। समस्त कार्यवाही की जानकारी अपीलान्ट को है। जांच दल प्रवर्तन निरीक्षको द्वारा सयुक्त रूप ने सही रिपोर्ट पेश की है। उपभोक्ताओं से प्राप्त शिकायतों के आधार पर अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र निलम्बित किया गया है। दौराने जांच रिथिति सही नहीं मिली जिसके आधार पर कार्यवाही की गई है और ना ही अपीलार्थी कार्यालय में उपस्थित हुआ। अतः अपील खारिज फरमाई जावें।


हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। दौराने बहस प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 जा0दी0 पेश हुआ नकल अपीलान्ट वकील को दिलाई गई

बहस प्रार्थना पत्र पर सुनी गई। प्रार्थना पत्र के प्रार्थी का हक हकूक प्रतीत नहीं होने के कारण प्रार्थना पत्र खारिज किया गया। जहाँ तक गुणावगुण का प्रश्न है अपीलान्ट ने अपील पेश कर मुख्य तर्क उठाया है कि अपीलान्ट के विरुद्ध कारण बताओं नोटिस दिनांक 9.7.20 जारी किया गया जिसका जबाब अपीलान्ट ने दिनांक 17.8.20 को जिला रसद अधिकारी के यहां पेश किया गया, जिस जवाब से संतुष्ट होकर जिला रसद अधिकारी ने दिनांक 17.8.20 को ही अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र बहाल करते हुए आदेश क्रमांक 28993 दिनांक 17.8.20 जारी किये गये थे। अपीलाधीन आदेश अपीलान्ट को बिना सुने पारित किया है तथा अपीलान्ट पर लगाये गये आरोप गंभीर प्रवृत्ति के नहीं हैं। जिसमें किसी प्रकार की अनियमितता नहीं बताई गई थी। अपीलान्ट द्वारा उठाये गये तर्क के सम्बन्ध में तहत अदालत की पत्रावली का अवलोकन किया। तहत अदालत द्वारा राजस्थान खाधान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के अन्तर्गत जारी अपीलान्ट के द्वारा प्राधिकार पत्र शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन पाये जाने के कारण प्राधिकार पत्र निलम्बित किया है। तहत अदालत में अपीलान्ट उपस्थित नहीं होने एवं जांच में सहयोग न करने तथा वितरण रिकॉर्ड प्रस्तुत नहीं किया गया, कोई युक्तियुक्त एवं औचित्यपूर्ण कारण प्रकट किया। विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपने कथन के समर्थन में प्रस्तुत दृष्टान्त में ऐसा नहीं है, कि अपीलान्ट जांच के दौरान जांच हेतु रिकॉर्ड उपलब्ध कराने उपभोक्ताओं के राशन कार्डों में अनियमितता करना में किसी न्यायालय द्वारा उक्त बिन्दुओं पर कोई सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया हो। अपीलान्ट इस तथ्य को साबित करने में असमर्थ रहा है। हम तहत अदालत के द्वारा पारित निर्णय में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं। अतः अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाकर जिला रसद अधिकारी के निर्णय दिनांक 24.08.20 यथावत रखा जाता है। निर्णय प्रति के साथ पत्रावली तहत वापस भिजवाई जावें। इस न्यायालय की पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्यर से कम हो, बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 11-08-2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



  
जिला कलेक्टर  
अलवर (राज.)  
जिला कलेक्टर, अलवर